हिसार का अधकचड़ा पावर प्लांट सरकार को सौंपने की तैयारी

जनता को निचोड़ने का यंत्र बना पॉवर हाऊस

हिसार (म.मो.) हरियाणा सरकार द्वारा खेदड़ में 600 गुणा 2 मेगावाट के पावर प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। रिलायंस एवं एक चीनी कंपनी द्वारा 4297 करोड़ की लागत से बनाया गया प्लांट पिछले कुछ माह से परीक्षण पर चल रहा है। परीक्षण की शर्तें पूरी न कर सकने के बावजूद इसे दो-चार दिन में ही सरकार को सौंप दिया जायेगा, बाद में सरकार जाने और प्लांट जाने, रिलायंस कंपनी का कोई लेना-देना नहीं।

परीक्षण की अन्य अनेक शर्तों के अलावा सर्वप्रथम शर्त यह है कि प्लांट को कम से कम 72 घंटे तक बिना ट्रिप हुए 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर के दिखाना चाहिए। पिछले काफ़ी दिनों से रिलायंस कंपनी इस शर्त को पूरा करने का प्रयास करती आ रही है, लेकिन कभी भी प्लांट 350 मेगावाट से अधिक उत्पादन नहीं कर सका। अब षडयंत्र यह रचा जा रहा है कि बॉयलर में कोयले के साथ-साथ भारी मात्राा में फर्नेस ऑयल झोंक कर बस एक बार 600 मेगावाट के लक्ष्य को छुआ कर रिलायंस अपनी जान छुटाना चाहती है। और यह भी क्या भरोसा है कि वास्तव में एक बार भी प्लांट ने लक्ष्य प्राप्त किया अथवा यह काम भी ले-दे कर काग़ज़ी ही होगा।

संदर्भवश पाठकों को अवगत करा दें कि यमुनानगर वाले प्लांट में परीक्षण के दौरान करीब 700 नुक्स (पंच प्वाइंट) निकले थे, जिन्हें निर्माता कंपनी को दुरुस्त करना था। बड़ी मुश्किल से रो-पीट कर 688 पंच प्वाइंट तो दुरुस्त हो गये थे, लेकिन 12 नुक्स ऐसे रह गये कि जो कंपनी द्वारा ठीक नहीं हो पाये। ऐसे में कंपनी ने सरकार से मिलीभगत कर के इस शर्त पर अपनी जान छुटाई कि इन 12 नुक्सों को कंपनी के खर्चे व जोखिम पर सरकार खुद ठीक करा ले। अब देखने वाली बात यह है कि जिन नुक्सों को निर्माता कंपनी ही ठीक नहीं कर सकी, उन्हें भला सरकार के अनाड़ी लोग़ कैसे ठीक कर सकते हैं? रही बात कंपनी के खर्चे व जोखिम पर काम कराने की तो यह बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि इस अवस्था तक कंपनी अपने ठेके अथवा हिस्से की 95 प्रतिशत रकम वसूल कर चुकी होती है। ऐसे में हज़ारों करोड़ रुपये के प्लांट में कंपनी का पैसा व जोखिम मात्र 50-60 करोड़ का ही रह जाता है, जबकि उन खामियों को दूर करने पर बेतहाशा पैसा खर्च हो सकता है। ऐसे में ये कंपनियां इस छोटी-मोटी रकम को छोड़ कर भागना ही बेहतर समझती हैं। यमुनानगर प्लांट में जो आये दिन ट्रिपिंग हो रही है और कभी भी प्लांट पूरी क्षमता पर नहीं चल पाता, इसका यही कारण है। और यह कारण स्थाई रूप से बना ही रहेगा। यमुनानगर से सबक सीख चुकी रिलायंस कंपनी ने खेदड़ प्लांट निर्माण का समझौता लिखते वक्त परीक्षण शर्तों को अपने अनुकूल बना लिया था। इसी के चलते अब कंपनी बहुत जल्दी यह कह कर मुक्ति पा लेगी कि जो कोई काम रह गया हो या कोई नुक्स पकड़ में आये, सरकार उसे स्वयं कंपनी के खर्चे व जोखिम पर करा ले। इसका परिणाम यह होना है कि 600 मेगावाट का यह प्लांट कभी भी 400 मेगावाट से अधिक उत्पादन नहीं दे पायेगा। जब कभी भी इसका लोड बढ़ाने का प्रयास जायेगा, यह ट्रिप कर जायेगा।

पिछले अंकों में लिखा जा चुका है कि प्लांट का एक बार ट्रिप करना कितना महंगा पड़ता है। यहां एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि कि यमुनानगर प्लांट से ठेकेदार (रिलायंस) कंपनी को मुक्त कर के सरकार आज तक भुगत रही है, उससे सरकार ने क्या सीखा? जो नुक्स सरकार यमुनानगर में आज तक दुरुस्त नहीं कर पाई, उन्हें खेदड़ में कैसे दुरुस्त कर लेगी?

ख़बर का असर बेअसर

पानीपत (म.मो.) गतांक में प्रकाशित किया गया था कि किस प्रकार प्लांट से निकलने वाली राखी को बेचने में कुछ लोग़ भारी घोटाला कर रहे हैं। इसका संज्ञान लेते हुए प्लांट के एक चीफ़ इंजीनियर सुरेश चंद्र वशिष्ठ ने इससे संबंधित दो व्यक्तियों - सर्वजीत व देसराज का तबादला कर दिया। लेकिन ये दोनों तो बेचारे केवल लूट का माल इकट्ठा करने वाले थे, असली माल खाने वाले तो ऊपर बैठे थे। ऊपर बैठने वालों में मुख्य हैं किन्नरा व अहलावत। जानकार बताते हैं कि इन दोनों ने अपने राजनीतिक आकाओं से दबाव बनवा कर उक्त दोनों कर्मचारियों का तबादला रुकवा दिया।

इससे सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार व लूटमार की जड़ें कितने गहरे तक बैठी हुई हैं। यदि कोई इक्का-दुक्का वशिष्ठ जैसा ईमानदार अफ़सर कुछ सुधर करने का प्रयास करना भी चाहे तो डकैतों का मजबूत गिरोह उसकी एक नहीं चलने देता। राखी का तो मात्र एक छोटा सा उदाहरण है, इन गिरोहों की पकड़ सारी व्यवस्था पर इतनी मजबूत है कि इन्हें कोई छेड़ भी नहीं सकता। जिस किसी ने भी इन्हें छेड़ने का प्रयास किया, ये लोग़ उलटे उसी को छेड़ देंगे।

यह भी प्रकाशित किया गया था कि चिमनी से निकलने वाले धुएं से राखी को अलग करने वाले ईएसपी के काम न करने से वातावरण में भारी प्रदूषण फ़ैल रहा है। वायुमंडल में जो राखीकण 100 से 150 एम.जी. होने चाहिए, वे बढ़ कर 1500-1600 एम.जी. होते हैं जिससे 20 किलोमीटर तक के इलाके में रहने वाले लोग़ पीड़ित हैं। नियमानुसार प्रदूषण विभाग द्वारा प्लांट से सैंपल भी लिये जाते हैं, जिन्हें भ्रष्ट अधिकारी रिश्वत के बल पर सहारनपुर की एक प्रयोगशाला से पास कराते रहे हैं। लेकिन अब उस प्रयोगशाला ने भी हाथ खड़े कर दिये हैं। अब देखना यह है कि अगले सैंपल कहां और कैसे पास होते हैं?

ठेकेदार कर रहा मनमानी

फरीदाबाद (म.मो.) पिछले दिनों कुमारी शारदा राठौड़, मुख्य संसदीय सचिव, हरियाणा सरकार ने शिव कॉलोनी, सेक्टर-22 में सीवर लाइन डालने के काम का शुभ मुहूर्त किया था।

संबंधित ठेकेदार ने सीवर लाइन डालने के लिए अच्छी-भली कामचलाऊ गलियों को जेसीबी द्वारा बीचोंबीच उखाड़ तो दिया, लेकिन जहां-जहां सीवर पाइप डाल दिये गये हैं, वहां-वहां से उन गलियों में उसने मिट्टी के ढेर लगा कर छोड़ दिये हैं, ना ही उसने उन खाइयों को अच्छी तरह भरवाया है। इस बरसात के मौसम में वैसे भी हमारी जल निकासी व्यवस्था चरमरा जाती है। उस पर इन गलियों की खाइयों में पानी भरेगा और मिट्टी के ढेर खाइयों के अलावा रास्ते पर भी कीचड़ फैलाने का काम करेंगे, जिसे किसी भी बड़ी दुर्घटना के होने का ख़तरा रहेगा। नगर निगम सें संबंधित एक्सईएन, एसडीओ अथवा जूनियर इंजीनियर, क्या किसी पर भी उस ठेकेदार के कार्य निरीक्षण करने की जिम्मेवारी नहीं है? जब दुर्घटना टाली जा सकती है तो क्या दुर्घटना होने का इंतज़ार करना जरूरी है?

किशोरों द्वारा वाहन चालन ट्रैफ़िक पुलिस तमाशबीन

फरीदाबाद (म.मो.) सरकार दुपहिया वाहन चलाने का लाइसेंस 18 वर्ष से कम आयु वालों का नहीं देती। यानी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति दुपहिया वाहन चलाने के हकदार नहीं हैं। पर सरकार के इस नियम की खुलेआम धड़ल्ले से अवहेलना होती है। 18 वर्ष से कम आयु के किशोर दुपहिया क्या चौपिहया वाहन तक खुलेआम चलाते हैं। लेकिन ट्रैफ़िक पुलिस इसे नज़रअंदाज कर देती है। वह उन्हें वाहन चलाने से रोकती नहीं है, बल्कि तमाशबीन बनी रहती है। साथ ही, बच्चों के माता-पिता यानी उनके अभिभावक भी अपने बच्चों को भारी-भरकम दुपहिया वाहन और चौपहिया वाहन चलाने से नहीं रोकते, बल्कि वे खुद उन्हें ड्राइविंग की ट्रेनिंग तक देते हैं। वे इस बात से गौरव महसूस करते हैं कि उनका बच्चा फर्राटे से भारी-भरकम बाइकों को उड़ा रहा है। जिन लोग़ों के पास कार है, उनके बच्चे कार चलाने की ट्रेनिंग अपने अभिभावकों से लेते हैं और भीड़ भरी सड़कों पर वाहन के साथ नमूदार हो जाते हैं। ये बच्चे निहायत ही गैरजिम्मेदाराना ढंग से सड़कों पर वाहन दौड़ाते हैं। इन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती कि गैरजिम्मेदाराना ढंग से वाहन चलाने का दूसरों पर कितना असर पड़ सकता है। अक्सर किशोर बाइकों से कलाबाज़ियां करते हैं और वह भी भीड़ भरे बाज़ारों में जिससे कभी-कभी दुर्घटना भी हो जाती है। पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बच्चे जब दुपहिया अथवा चौपहिया वाहनों को चलाते हैं तो निर्धारित से अधिक गति से उन्हें चलाते ही हैं, सड़कों पर उन्हें आड़े-तिरछे दौड़ाते भी हैं। इससे बराबर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।

सरकार ने 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को बिना गियर वाले वाहन चलाने की छूट दे रखी है, यानी उन्हें चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि लाइसेंस लिया जाये। पर अब तो नई तकनीकों के लगातार सामने आने से ऐसे कई बिना गियर वाले दुपहिया वाहन मौजूद हैं जो देखते ही देखते हवा से बातें करने लगते हैं। इन वाहनों पर बच्चे काफ़ी मस्ती करते हैं। लेकिन आफत तो तब आती है जब ये बच्चे बाइक रेसिंग में लग जाते हैं। देखा जाये तो वे पल भर के रोमांच के लिये अपने साथ-साथ ही दूसरों के लिए बड़ा ख़तरा मोल लेते हैं। जहां तक भारी-भरकम वाहनों को चलाने से बच्चों को रोकने का सवाल है तो यह काम अच्छी तरह उनके अभिभावक ही कर सकते हैं, पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वे इस पर जरा भी ध्यान नहीं देते। ऐसे में यह कार्य ट्रैफ़िक पुलिस का होना चाहिए जो नियम विरुद्ध वाहन चलाने वालों की धर-पकड़ करे। लेकिन ट्रैफ़िक पुलिस इस समस्या पर ध्यान ही नहीं देती। अगर ट्रैफ़िक पुलिस इस समस्या पर ध्यान दे और बिना लाइसेंस के भारी दुपहिया एवं चौपहिया चलाने वाले कम उम्र किशोरों की धर-पकड़ करे तो यह समस्या आसानी से सुलझ सकती है। यह बात ध्यान में रखने की है कि किशोरों द्वारा गैरजिम्मेदाराना ढंग से वाहन चलाने के कारण अनेकों दुर्घटनायें होती हैं। इसलिये यह ट्रैफ़िक पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह किशोरों द्वारा वाहन चलाने पर सख़्त पाबंदी लगाये।

बार-बार शिकायत के बावजूद बिजली विभाग ने नहीं ली सुध

पलवल (म.मो.) आजकल बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता समाचार पत्रों में प्रतिदिन अपने अधीन अधिकारियों के टेलीफोन नंबर जनता की बिजली संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु छपवा रहें हैं ताकि आम लोग अपनी बिजली ख़राब होने पर उन नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा कर बिजली ठीक करवा सकें। लेकिन यह सारा प्रचार जनता की आँखों में धूल झोंकने के लिए है। इसी तरह पहले भी नंबर छपवाए जाते रहे हैं, ऐसे ही छपे नंबरों पर अपनी बिजली ख़राब होने की शिकायत करके एक उपभोक्ता इनकी वास्तविकता से रूबरू हो चुका है और सबसे बड़ी बात तो ये रही की इन्ही अधीक्षक अभियंता को ही चार पांच बार टेलीफोन करना पड़ा और अंतिम बार तो दो टूक बात करने पर बिजली तीन घंटे बाद ठीक की गई। इसी आठ जून को पलवल में रहने वाले एक उपभोक्ता अजय सिंह की बिजली सुबह सात बजे ख़राब हो गई उन्होंने पहले तो इंतजार किया कि हो सकता है की शायद बिजली पीछे से ही चली गई होगी एक घंटे तक भी जब बिजली नहीं आई तो उन्होंने पड़ोसियों के वहां से पता किया तो बिजली आ रही थी उन्हें अपने ऑफिस गुड़गाँव जाना था। उनके पास समय कम था इसलिए उन्होंने पहले तो बिजली शिकायत केंद्र में टेलिफोन मिलाया। वहां पर टेलिफोन न मिलने पर उन्होंने कंट्रोल रूम में टेलिफोन किया। वहां से जबाब मिला कि शिकायत केंद्र का टेलिफोन ख़राब है इसलिए आप जे ई के

बिजली विभाग के इन अधिकरियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने अधीनस्थ एक अदने से जेई से एक उपभोक्ता कि बिजली को तेरह घंटे तक ठीक न करने का कारण पूछ सकें। बस समाचार पत्रों में ख़बरें छपवा कर जनता कि आंखों में धूल झोंकते रहते हैं।

नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करवा दें। वहां से जेई का नंबर ले कर जेई को टेलिफोन करके अपनी बिजली ख़राब होने की बात बताई। जे ई ने ऑफिस जाकर कार्रवाई करने कि बात कही। जेई की बात पर विश्वास करके वह अपने ऑफिस गुडगाँव चले गए। दो घंटे बाद भी जब बिजली ठीक नहीं हुई तो उन्होंने फिर जेई को फोन किया लेकिन जेई ने फोन ही नहीं उठाया। इस पर उन्होंने एसडीओ का फोन नंबर लेकर उन्हें फोन किया तो उनका फोन बंद मिला। इस पर उन्होंने एक्सइएन के कार्यालय में फोन किया तो बताया गया की वे चुनाव ड्यूटी पर गए हैं। एक्सइएन ऑफिस में अपनी शिकायत बताई वहां से आश्वासन दिया कि जल्दी ठीक करवाते हैं लेकिन दो बजे तक भी जब बिजली ठीक नहीं की गई तो उन्होंने फिर एक्सइएन को फोन किया इस बार फोन मिल गया। उनकी शिकायत पर उनका जबाब था कि मेरी ड्यूटी चुनावों में लगी हुई है इसलिए वे चुनावों के बाद बात करेंगे। अब चुनाव दस जून को होने थे इसके बाद कहीं से इन्ही एसई साहब का नंबर लेकर इन्हें अपनी शिकायत सुबह से लेकर दोपहर बाद तक कि पूरी बात बताई। इन्होंने आश्वासन दिया कि अभी एक्सइएन से बात करता हूं कि उन्होंने इस तरह का जबाब कैसे दिया है। लेकिन बिजली साढ़े चार बजे तक भी ठीक नहीं की गई। इस पर फिर एसई साहब को फोन किया तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में गाड़ी चला रहें हैं आपकी बिजली जल्दी ठीक हो जाएगी लेकिन बिजली सायं साढ़े पांच बजे तक भी ठीक नहीं कि गई घर पहुंच कर उन्होंने शिकायत केंद्र पर जाकर शिकायत लिखी तथा एक्सइएन ऑफिस जाकर एक्सइएन को ढूंढा वे वहां नहीं थे। उनके सहायक से बात हुई उन्होंने वहीं से जेई को फिर कहा कि सुबह से अब तक बिजली ठीक नहीं की गई है, इसे जल्दी ठीक करवा दें लेकिन आठ बजे तक भी बिजली ठीक नहीं कि गई। इसके बाद इन्ही एसई साहब से जब दो टूक शब्दों में बात की उसके बाद भी लगभग एक घंटे बाद उनकी बिजली ठीक की गई। इस तरह पूरे तेरह घंटा इस भयंकर गर्मी में बिना पानी के एक उपभोक्ता का परिवार रहा। यह है एसई साहब के ड्रामे कि वास्तविकता। बिजली विभाग के इन अधिकरियों में इतनी हिम्मत नहीं है कि वे अपने अधीनस्थ एक अदने से जेई से एक उपभोक्ता कि बिजली को तेरह घंटे तक ठीक न करने का कारण पूछ सकें। बस समाचार पत्रों में ख़बरें छपवा कर जनता कि आंखों में धूल झोंकते रहते हैं।